12. Professor R.L. Singh Department of Philosophy Allahabad University, Allahabad (U.P.)

13. Professor Indra Bhushan Pande Department of Philosophy Lucknow University Lucknow (U.P.)

Levy of Education Cess

*151. SHRI N.R. DASARI:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased state:

(a) whether Government are considering a proposal to levy an education cess to raise resources for elementary education programmes; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) National Policy on Education, 1986 visualises "levying of cess or charge" to mobilise resources for this purpose. Operationalisation of this vision is a matter of detail which the Government would keep in view.

जनसंख्या नियंत्रण और महामारियां

*152. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय इमरजेंसी के तौर पर लेने का आग्रह किया है;

(ख) क्या उक्त एसोसिएशन के मतानुसार "वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य मात्र एक सपना ही बनकर रह जाएगा;

(ग) क्या उक्त एसोसिएशन के मतानुसार "एडस" हेपाटाइटिस, हैजा, क्षयरोग, मलेरिया जैसे रोग फिर से महामारी का रूप ले चुके है;और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन मुदों के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) भारतीय चिकित्सा संघ ने 27 दिसम्बर, 1998 को हुए अपने सम्मेलन में देश के जनसंख्या परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया और सुझाव दिया कि इसे राष्ट्रीय आपातकाल माना जाए।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा संघ ने उपर्युक्त सम्मेलन में इस प्रकार के कोई संकल्प पारित नही किए गए है।

(घ) भारत सरकार को जनसंख्या के इस नाजुक स्वरूप की पूरी-पूरी जानकारी है। सरकार ने इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है। 1998-99 में परिवार कल्याण के लिए बजट आवंटन में 6.60 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की गई जिसमें 1999-2000 में 4.31 करोड़ रुपये की और वृद्धि की जा रही है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं; जिनमें जनसंख्या नियंत्रण संबंधी सेवाएं शामिल हैं को देश भर में सुदृढ़ किया जा रहा है।

संसद ने स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने विशेष सत्र के दौरान जनसंख्या स्थिति पर एक विषय के रूप में विचार-विमर्श किया। सरकार ने राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के परामर्श से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की है। सरकार आशा करती है कि वह संसद के समक्ष शीघ्र ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रस्तुत कर पायेगी।

Selection grade posts of Yoga Teachers

*153. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether following implementation of the Third Central Pay Commission's recommendations, 20% of the total posts of different cadres were converted into Selection Grade Posts;

(b) if so, whether posts of Yoga teachers were also converted under this provision; and

(c) if not, the reasons and rationale therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) The scheme of selection grades in Group 'C' and 'D' cadres ranging from 10% to 20% on the recommendations of the Third Central Pay Commission was introduced by the Government with effect from 1.8.1976 subject to certain conditions.

(b) and (c) The Government of NCT of Delhi have informed that 91 out of 457 posts of Yoga teachers first recruited in 1982-83 have been converted into selection grade posts. Further, that no recruitment of Yoga teachers has been made after 1982-83. The UTs of Pondicherry, Lakshadweep, Andaman & Nicobar
Islands have reported that the posts of Yoga teachers do not exist in their schools. In the UT of Chandigarh, the Central Pay Commission scales of pay are not applicable.

Like-wise the autonomous school systems of Navodaya Vidyalayas and Central Tibetan Schools have reported that there are no posts of Yoga teachers in their schools. The KVS have informed that the scheme of Yoga teachers was introduced on an experimental basis in 1981 and extended on year to year basis till its review by the Board of Governors in 1986 when it was decided that Yoga be integrated with Physical Education Programme of Kendriya Vidyalayas and that Yoga teachers be directed to obtain the minimum academic and professional qualifications prescribed for Physical Education Teachers within a period of three years. The eligible Yoga teachers in Kendriya Vidyalayas have been granted three-tier pay scale structure w.e.f. 1.1.1996.

पर्यावरण पर पर्यटन का प्रभाव

*154. **श्री रमा शंकर कौशिक** :
प्रो0 रामगोपाल यादव :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" में "पर्यटन से सत्यानाश होता पर्यावरण" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार अमूमन पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में ही होटल खोलने और वहां आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का काम करती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के ऐसे प्रयासों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) जी, हां। पर्यटन विकास को पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल ढ़ंग से विनियमित करने के लिए हाई टाईड-लाईन (एच0टी0एल0) के 200 मीटर से 500 मीटर के बीच अथवा 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर और 5 करोड़ रु0 से अधिक के निवेश की पर्यटन परियोजनाओं के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सी0आर0जैड0) अधिसूचना, 1991 और/अथवा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई0 आई0 ए0) अधिसूचना 1994 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय की पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित है । पर्यटन परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरणीया मंजूरी देते समय, आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाते हैं । पर्यटन विकास कार्य को पर्यावरणीय दृष्टि से स्थायी ढ़ंग से समन्वित करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय निरंतर एक दूसरे से सम्पर्क बनाए रखते है।

Lack of Software for Indian Languages

*155. DR. C. NARAYANA REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the context of globalization and explosion of Information Technology, the Indian languages are at a disadvantageous position due to lack of adequate software;

(b) whether it is likely to lead to a stage where the Indian languages will lose their rightful place; and